

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267] No. 267] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 11, 2016/श्रावण 20, 1938

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 11, 2016/SRAVANA 20, 1938

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2016

# जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

विषय : भारत में चीन जन. गण., के मूल की या वहां से निर्यातित 1-फिनाइल-3-मिथाइल-5-पाइराजोलोन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत

संख्या 15/3/2016-डीजीएडी.— 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने दिनांक 16 नवम्बर, 2005 की अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना सं. 14/11/2004-डीजीएडी द्वारा चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल की या वहां से निर्यातित 1-फिनाइल-3-मिथाइल-5-पाइराजोलोन (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। प्राधिकारी के जाँच परिणाम के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 10 जनवरी 2006 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 1/2006 द्वारा संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. प्राधिकारी ने दिनांक 1 जुलाई, 2010 की अधिसूचना सं. 15/5/2010-डीजीएडी द्वारा निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरूआत की। प्राधिकारी ने दिनांक 29 जून, 2011 की अधिसूचना सं. 15/5/2010-डीजीएडी द्वारा चीन जन

3992 GI/2016 (1)

गण से आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की और राजस्व विभाग ने चीन जन गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर दिनांक 24 अगस्त, 2011 की अधिसूचना सं. 80/2011-सीमाशुल्क द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया था।

3. यत:, विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन को ध्यान में रखते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पिठत अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इस बात की जाँच करने कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की आशंका है, के लिए निर्णायक समीक्षा की शुरूआत करते हैं।

# घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

- 4. यह याचिका मैं. प्राइमा कैमिकल्स और मैं. पालीगान कैमिकल्स द्वारा दायर की गई है। तथापि 1 अप्रैल, 2016 और उसके बाद की स्थिति के अनुसार, पालीगान कैमिकल्स का प्राइमा कैमिकल्स में विलय हो गया है।
- 5. रिकार्ड में दिए गए अनुरोधों के अनुसार आवेदक कंपनियों का उत्पादन घरेलू उत्पादन का "प्रमुख हिस्सा" बनता है और इसलिए आवेदक कंपनियां पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

# विचाराधीन उत्पाद

- 6. विचाराधीन उत्पाद 1-फिनाइल-3-मिथाइल-5-पाइराजोलोन है। 1-फिनाइल-3-मिथाइल-5-पाइराजोलोन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयोग रंजक मध्यवर्ती के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग एनलजीन के उत्पादन के लिए भेषजों में भी होता है।
- 7. 1-फिनाइल-3-मिथाइल-5-पाइराजोलोन को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अधीन सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 2933 19 20 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और संबद्ध जाँच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।
- 8. चूंकि यह ऐसे उत्पाद के संबंध में निर्णायक समीक्षा जाँच है जिसपर पाटनरोधी शुल्क पहले से लागू है इसलिए विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा मूल जाँच में किए गए उल्लेख के समान है।

## शामिल देश

9. वर्तमान जांच चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन से संबंधित है।

#### सामान्य मूल्य

10. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और चीन के संबंध में नियमावली के अनुबंध । के पैरा 7 और 8 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदकों ने भारत में उत्पादन लागत को विधिवत रूप से समायोजित करके चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य का दावा किया है। नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 के अनुसार यह माना जाता है कि चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के अधीन कार्य कर रहे हैं। उक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता और चीन जन. गण. में प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा उसके खंडन के अधीन चीन जन. गण. के लिए संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का अनुमान नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है।

## निर्यात कीमत

11. याचिकाकर्ताओ द्वारा भारत में संबद्ध आयात की मात्रा और मूल्य का आकलन करने के लिए आईबीआईएस से प्राप्त सौदा-वार आयात सूचना को प्रस्तुत किया है। निर्यात कीमत को भारित औसत आयात कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए निर्यात कीमत को समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतरर्देशीय भाड़े, बैंक प्रभार के लिए समायोजित किया गया है।

# पाटन मार्जिन

12. सामान्य मूल्य और कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत की तुलना की गई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से अधिक है जिससे पता चलता है कि संबद्ध देश में निर्यातकों के द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

# जांच अवधि (पीओआई)

13. वर्तमान जॉंच के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तावित जांच अविध (पीओआई) अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 (12 महीनों) की है और क्षित जॉंच अविध में अप्रैल 12 से मार्च 13, अप्रैल 2013- मार्च 2014, अप्रैल 2014- मार्च 2015 और जांच अविध शामिल है।

# सूचना प्रस्तुत करना

14. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जिरए संबद्ध देश की सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:-

# निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग चौथा तल , जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

15. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धित से प्रस्तुत कर सकता है।

# समय-सीमा

- 16. वर्तमान जॉंच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
- 17. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरूआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

# अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

18. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में" गोपनीयता "का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक ,सूची ,पृष्ठ संख्या आदि);

- और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक ,सूची ,पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए।
- 19. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमित देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की पाँच (5)प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।
- 20. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।
- 21. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है ,पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध /रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि ,आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों सभव नहीं है।
- 22. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
- 23. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

# सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

24. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

## <u>असहयोग</u>

25. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अविध के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यिधक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

#### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

#### **Department Of Commerce**

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

New Delhi, the 11th August, 2016

#### INITIATION NOTIFICATION

Subject: Initiation of Sunset Review Investigation of Anti-dumping duty on import of 1-Phenyl-3-Methyl-5-Pyrazolone originating in or exported from China PR in India.

**No. 15/3/2016- DGAD.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Designated Authority (hereinafter referred to as Authority) recommended imposition of Anti-Dumping Duty on imports of 1-Phenyl-3-Methyl-5-Pyrazolone (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as subject country) vide final findings notification No. 14/11/2004-DGAD dated 16<sup>th</sup> November 2005. Based on the findings of the Authority, definitive anti-dumping duties on the subject goods imported from subject country was imposed by the Department of Revenue vide Customs notification No. 1/2006 dated 10<sup>th</sup> January 2006.

- 2. The Authority initiated sunset review investigations vide Notification No. 15/5/2010- DGAD dated 1<sup>st</sup> July 2010. The Authority recommended continuation of imposition of definitive anti-dumping duties on imports from China PR vide notification No.15/5/2010- DGAD, dated 29<sup>th</sup> June, 2011 and the Department of Revenue imposed definitive anti-dumping duty vide notification No. 80/2011-Customs, dated the 24<sup>th</sup> August, 2011 on all imports of subject goods originating in or exported from China PR.
- 3. Whereas, in view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry

#### **Domestic Industry & Standing**

- **4.** The petition has been filed by M/s. Prima Chemicals and M/s. Polygon Chemicals. However, as of 1<sup>st</sup> April 2016 and henceforth, Polygon Chemicals has merged with Prima Chemicals.
- 5. As per the submission on record, the production of the applicant companies constitutes "a major proportion" of the domestic production and, therefore, the applicant companies constitute eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti-Dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

#### **Product under consideration**

- **6.** The product under consideration is 1-Phenyl-3-Methyl-5-Pyrazolone. 1-Phenyl-3-Methyl-5-Pyrazolone is an organic compound which finds application as a dye intermediate. It is also used in Pharmaceuticals for production of Analgin.
- 7. 1-Phenyl-3-Methyl-5-Pyrazolone is classified under Customs sub heading No. 2933 19 20 under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975. However, Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the subject investigation
- **8.** This being a Sunset Review of the product on which Anti-Dumping Duty is already in force, the definition of the Product under consideration is the same as mentioned in the original investigation.

#### **Countries involved**

**9.** The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from China PR.

#### **Normal Value**

10. The applicants have claimed that China PR should be treated as a non-market economy and determined normal value in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. The applicant has claimed normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted. In terms of Para 8 in Annexure 1 to the Rules it is presumed that the producers of the subject goods in China PR are operating under non-market economy conditions. In view of the above non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters from china PR, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.

#### **Export Price**

11. The Petitioners have submitted the IBIS transaction-wise import information to assess the volume and value of the subject import in India. Export price has been determined on the basis of weighted average of the import price. Export price has been adjusted for Ocean Freight, Marine Insurance, Commission, Port Expenses, Inland Freight and Bank Charges to arrive at the net export price.

#### **Dumping Margin**

12. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country are higher than the ex-factory export price, indicating, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country. The dumping margins are estimated to be above de minimis.

#### **Period of Investigation (POI)**

13. The Period of Investigation (POI) proposed by the applicant is from April 2015 to March 2016 (12 months) and the injury investigation period is for the periods, Apr'12-Mar'13, Apr'13-Mar'14, Apr'14-Mar'15 and the Period of Investigation.

#### **Submission of information**

14. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

## The Designated Authority,

Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties,

Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce

4th Floor, Jeevantara Building,

#### 5 Parliament Street, New Delhi -110001

15. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

#### **Time limit**

- 16. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.
- 17. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

## **Submission of Information on Non-Confidential basis**

- 18. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.
- 19. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.
- **20.** For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
- 21. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
- 22. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
- 23. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

#### **Inspection of Public File**

**24.** In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

#### **Non-cooperation**

25. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A. K. Bhalla, Addl. Secretary & Designated Authority